RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 170
दि. 25.03.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


## धर्मांतरण पर सुप्रीम फैसला: धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा SC-एसटी एक्ट का लाभ

मुंबई/नई दिल्ली। भारत के संवैधानिक और सामाजिक परिदृश्य में अनुसूचित जातियों (SC) को मिलने वाले अधिकारों और आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2026 को एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने धर्मांतरण और SC-एसटी एक्ट के लाभों के बीच स्पष्ट रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा केवल तभी दिया जा सकता है जब वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करता हो। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेता है, तो उसका SC दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है और वह न तो आरक्षण का लाभ उठा सकता है और न ही एससी-एसटी एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का अधिकार रखता है।

यह मामला एक ईसाई पादरी से जुड़ा था, जिसने एससी-एसटी एक्ट के तहत अपना हक पाने के लिए न्यायालय का रुख किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई आधिकारिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए धर्म परिवर्तन के बाद SC वर्ग का लाभ देना संविधान और कानून दोनों के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही तर्क सही माना और स्पष्ट किया कि धर्म बदलने के बाद व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता और न ही उसे संबंधित आरक्षण या अन्य लाभ मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव देशभर में SC वर्ग के उन लोगों पर पड़ेगा, जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं या पहले ही अपनाकर लाभ उठा रहे हैं। इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद SC वर्ग का दर्जा केवल उसी स्थिति में बरकरार रहेगा जब व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अंतर्गत किसी जाति में हो और धर्म परिवर्तन उसी तीन धर्मों के भीतर हो। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित होता है, तो उसका SC दर्जा बना रहेगा और वह आरक्षण व कानूनी सुरक्षा का लाभ ले सकता है।

इसके विपरीत, जो लोग इन तीन धर्मों को छोड़कर अन्य धर्मों में जाते हैं, उन्हें न केवल आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा, बल्कि उन्हें एससी-एसटी एक्ट के तहत मिलने वाली सुरक्षा का भी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, ऐसे धर्मांतरित व्यक्ति अपने नए धर्म या राज्य के नियमों के तहत अन्य श्रेणियों, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या सामान्य वर्ग के तहत मिलने वाले लाभों के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन यह लाभ SC वर्ग के अधिकारों के समकक्ष नहीं होगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला समाज में जातिगत पहचान और अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक स्पष्ट संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान और संबंधित कानून SC वर्ग के लाभों को धर्म की सीमाओं के अनुसार संरक्षित करते हैं। इस फैसले का उद्देश्य न केवल कानूनी स्पष्टता प्रदान करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि अनुसूचित जातियों को मिलने वाले अधिकार उनके मूल धर्म और सामाजिक संरचना के आधार पर ही मान्य हों।

इस फैसले को सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह उन विवादों और कानूनी मामलों को सुलझाने में मार्गदर्शन करेगा, जहां धर्मांतरण और जाति-आधारित आरक्षण के अधिकारों पर सवाल उठते रहे हैं। न्याय विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आगे आने वाले वर्षों में धर्मांतरण से जुड़े SC वर्ग के मामलों के लिए मिसाल साबित होगा और समान परिस्थितियों में न्यायपालिका का मार्गदर्शन करेगा।

सरकार और राज्य प्रशासन को भी इस फैसले के बाद नीति और आरक्षण के नियमों को स्पष्ट रूप से लागू करना होगा। SC वर्ग के लिए लाभार्थी सूची, आरक्षण की प्रक्रिया और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधान अब इस फैसले के अनुरूप संशोधित किए जाएंगे, ताकि कोई कानूनी जटिलता या अस्पष्टता न रहे।

यह फैसला भारत में अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण और कानूनी सुरक्षा के मामलों में एक निर्णायक मील का पत्थर है। न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्मांतरण और जाति पहचान के अधिकार सीधे जुड़े हैं, और कोई भी व्यक्ति जब तक हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अंतर्गत नहीं है, वह SC वर्ग के लाभों का हकदार नहीं होगा। इस निर्णय से समाज में अधिकारों की स्पष्टता बढ़ेगी और संभावित विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।

## "द यश मंगलम शो" की नई लघु फिल्म "युवा बिहार" में युवा पीढ़ी के जज़्बे और जुनून की असरदार अभिव्यक्ति, "बिहार दिवस" पर पटना में हुआ शानदार लोकार्पण

मुंबई, 24 मार्च। भारत के ऐतिहासिक प्रदेश बिहार के स्थापना दिवस की वर्षगाँठ के अवसर पर इंटरनेट के लोकप्रिय माध्यम यू-ट्यूब पर एक सुरुचिपूर्ण लघु फिल्म "युवा बिहार का लोकार्पण हुआ, जिसमें बिहार की युवा पीढ़ी के अद्भुत हुनर एवं बुलंद हौसलों के साथ युवाओं के जोश, जज़्बे और जुनून की असरदार अभिव्यक्ति की गई है। पिछले दिनों जारी विभिन्न लघु फिल्मों को मिली निरंतर सफलता के बाद सृजनात्मक उत्कृष्टता के एक सशक्त ब्रांड के रूप में लोकप्रिय होते जा रहे "द यश मंगलम शो" की नवीनतम कड़ी के रूप में इस लघु फिल्म " युवा बिहार" का लोकार्पण बिहार दिवस के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के टेन्डर हार्ट्स इंटरनेशनल, स्कूल में किया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने भी इस जोशीली लघु फिल्म का अवलोकन कर इसकी सृजनात्मक उत्कृष्टता को सराहा है।

एक अनूठी सृजनात्मक पहल के अंतर्गत "वाइब्रेशन्स मीडिया वर्क्स, मुंबई" द्वारा "महतपुरकर एंड मंगलम फाउंडेशन" के बैनर तले नवसृजित यह अद्भुत लघु फिल्म "युवा बिहार" सोशल मीडिया के सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म यू-ट्यूब पर मौजूद

सुरुचिपूर्ण चैनल "द यश मंगलम शो' के अंतर्गत अपलोड की गई है, जो अपने अनूठे कंटेंट और प्रस्तुतीकरण के विलक्षण अंदाज़ के लिए काफी लोकप्रिय है और व्यापक तौर पर सराहा जाता रहा है। इससे पहले इस लोकप्रिय शो की "धरोहरः ए पोएटिक सागा", *"शिल्पकार", "योगा रिट्रीट", "सेहत के रखवाले", *कारगिल विजय दिवस- ए पोएटिक सागा, "मैं भारत हूँ..!", *"पथ प्रदर्शक"* " द लीगेसी ऑफ मैथेमेटिक्स" और "वंदे मातरम" जैसी प्रभावशाली कड़ियाँ यू-ट्यूब पर काफी अच्छा प्रतिसाद पा चुकी हैं। इस शो के जोशीले और युवा शो-बॉय यश मंगलम हैं, जो सिर्फ़ 16 वर्ष की आयु में ही अपनी दमदार आवाज़, आकर्षक व्यक्तित्व और सशक्त प्रस्तुतीकरण से अपनी शानदार शैली की बदौलत शो- बिज़ की दुनिया में अपने पैर बखूबी जमा रहे हैं। इस विशेष लघु फिल्म का प्रभावशाली लेखन मुंबई के सुपरिचित गीतकार, मंच संचालक तथा मीडिया एवं जनसम्पर्क सलाहकार गजानन महतपुरकर ने किया है, जिसमें बिहार राज्य के गौरवशाली इतिहास और इसके राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पहलुओं को बखूबी पिरोया गया है। उल्लेखनीय है कि गजानन महतपुरकर द्वारा लिखी गई 12 से अधिक लघु फिल्में पहले ही यू-ट्यूब पर धूम मचा चुकी हैं। इसी क्रम में अब नवीनतम लघु फिल्म के ज़रिये गजानन महतपुरकर की सशक्त लेखनी और सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अनुपम मंगलम के कुशल निर्देशन का कमाल यू-ट्यूब पर लोकप्रिय हो रहा है। इस सशक्त, प्रभावशाली और संवेदनशील लघु फिल्म को अपने कुशल निर्देशन के ज़रिये पर्दे पर उतारने का दायित्व बखूबी निभाया है, मुंबई के विज्ञापन एवं फिल्म जगत के भरोसेमंद निर्देशक अनुपम मंगलम ने, जिनको पिछले 25 सालों में 300 से ज्यादा विज्ञापन फिल्में बनाने का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। वरिष्ठ राजनेता श्री राजाराम पांडेय जी की संकल्पना पर आधारित इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री जय कपूर हैं। इसके एसोसिएट प्रोड्यूसर श्री राजीव भार्गव और क्रिएटिव डायरेक्टर सुश्री रत्ना नीलम पांडे हैं। इस नवसृजित लघु फिल्म का भावपूर्ण पार्श्व संगीत समीर पखाले ने दिया है। वीडियोग्राफी संजय वैष्णव, वी एफ एक्स संयोजन गिनीलाल सालुंके, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कला मंगलम और एडिटिंग प्रताप शिंदे द्वारा सुनिश्चित की गई है। पोस्ट प्रोडक्शन "वाइब्रेशन्स मीडिया वर्क्स, मुंबई" ने किया है। बिहार दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर जारी इस विशेष लघु फिल्म को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और इसकी विलक्षण गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। इस ऊर्जावान लघु फिल्म का प्रदर्शन म्यूज़ियम, बिहार के अनेक विद्यालयों और पटना के विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। इस लघु फिल्म की प्रमुख पंक्तियाँ कुछ इस तरह रची गई हैं :- सच बताइये दोस्तों ! क्या बिहार सिर्फ एक जगह का नाम है ? या फ़िर एक सोच की शैली या एक अनूठी शक्ति का भंडार जिसे है सही वक़्त का इन्तज़ार..! ये राज्यसिर्फ ज़मीन नहीं है, ये मेमोरी है...! ये मूवमेंट है...! ये समय के कैनवास पर जाँबाज़ इरादों का स्टेटमेंट है..! जो कभी रुकता नहीं ! कभी थकता नहीं...! कभी झुकता नहीं..! दोस्तों, अपना बिहार सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं, बल्कि इंडियन फ्यूचर के नैक्स्ट चैप्टर का टाइटल है......बिहार...! भारतीय संस्कृति के धरातल पर है बुलंद हौसलों की हुंकार..! ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं.... चिंगारी है, आज हर टेलेंट की पूरी तैयारी है, ये युवा बिहार है मित्रों अब हमारी बारी है..!

यह लघु फिल्म इस यू-ट्यूब लिंक पर देखी जा सकती है :-

https://youtu.be/Ec2e9-rnX80?si=t_h-ZvdfYEHBs7qE

## पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में एसआईआर सुचारू: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतदान से जुड़ी मतदाता सूची की स्थिति पर अहम टिप्पणियां करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास अधिकांश राज्यों में सुचारू रूप से पूरा हुआ है, केवल पश्चिम बंगाल इसे छोड़कर। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों में एसआईआर अभ्यास के दौरान कोई गंभीर विवाद या मुकदमेबाजी सामने नहीं आई, जबकि पश्चिम बंगाल में कुछ अनियमितताओं की शिकायतें दर्ज की गई हैं।

सीजेआई ने इस दौरान कहा कि अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जटिल जरूर थी, लेकिन कुल मिलाकर यह बिना बाधा और सुचारू रूप से चली। न्यायालय की यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि राज्य में मतदाता सूची को लेकर कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता और वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने अदालत से अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदाता सूची पर रोक की तारीख बढ़ाई जाए, ताकि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं या विवाद के कारण शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें जोड़ने का मौका दिया जा सके। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत इस पर उचित निर्णय लेगी। कोर्ट ने फिलहाल स्थिति को अनुकूल बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हुआ, तो वे किसी भी समय इस पर विस्तृत निर्देश जारी कर सकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी यह दर्शाती है कि भारत के अन्य राज्यों में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अपेक्षाकृत व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल में कुछ अनियमितताएं चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए चुनौती बन सकती हैं। इस मामले पर अदालत की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते सुधारने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके।

न्याय विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया यह रुख चुनाव आयोग और संबंधित राज्यों को मतदाता सूची में पारदर्शिता बनाए रखने और सभी पात्र मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि किसी भी राज्य में एसआईआर में असंगतियों को लेकर उचित समय और संसाधनों के साथ कार्रवाई की जाएगी ताकि मतदाता सूची पूरी तरह निष्पक्ष और भरोसेमंद बनी रहे।

इस निर्णय से साफ है कि देश के चुनावी ढांचे में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता है, और पश्चिम बंगाल में हुई असंगतियों पर भी अदालत सख्त नजर बनाए हुए है। इसे भविष्य में किसी भी राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिससे सभी राज्यों में समान रूप से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

## सीमाओं से समृद्धि तक: सीमावर्ती गांवों के लिए विकास की नई सोच और बदलती रणनीति

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वर्षों से चल रहे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसके साथ ही सरकार ने एक नई सोच के तहत सीमावर्ती गांवों को केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि 2004-05 से अब तक इस योजना के तहत 39 हजार से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसने देश की सीमाओं पर बसे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में लिखित जवाब के जरिए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ना रहा है। यह कार्यक्रम 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों और कस्बों में लागू किया गया, जिसमें 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इस दौरान सड़क, पुल, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनवाड़ी और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे इन क्षेत्रों में जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला।

हालांकि अब यह योजना 'सनसेट फेज'

में पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि नई परियोजनाओं की मंजूरी की बजाय पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 168.90 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो मुख्य रूप से अधूरे कार्यों और देनदारियों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार अब सीमावर्ती विकास के अगले चरण की ओर बढ़ रही है, जहां केवल ढांचागत विकास ही नहीं, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता पर भी फोकस किया जाएगा।

दरअसल, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की कहानी केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है। इन इलाकों में लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं की कमी, रोजगार के अवसरों का अभाव और पलायन जैसी समस्याएं बनी रही हैं। यही कारण है कि अब सरकार ने अपनी रणनीति को बदलते हुए इन क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी सोच के तहत वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जो सीमावर्ती गांवों को 'जीवंत' और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

इस नई योजना के तहत 2023 में उत्तरी सीमाओं पर स्थित 662 गांवों को चुना गया, जहां आधारभूत संरचना के साथ-साथ पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग और कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। इसके बाद 2025 में इसके दूसरे चरण यानी वीवीपी-II में 1,954 गांवों को शामिल किया गया, जिसमें भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्र भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम 2028-29 तक चलेगा और इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को इस तरह विकसित करना है कि वे केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सकें।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल योजनाओं का नहीं, बल्कि सोच का भी है। पहले जहां सीमावर्ती इलाकों को केवल सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, वहीं अब उन्हें विकास के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और उन्हें बेहतर जीवन सुविधाएं मिलेंगी, तो वे अपने क्षेत्रों को छोड़कर पलायन नहीं करेंगे, जिससे सीमा क्षेत्र अधिक सुरक्षित और स्थिर बनेंगे।

इसके अलावा, नई रणनीति में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी महत्व दिया गया है। गांवों के विकास में स्थानीय लोगों को शामिल कर उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई जा रही हैं। इससे न केवल योजनाओं का प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति जुड़ाव भी मजबूत होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।

सरकार की इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि सीमावर्ती इलाकों को देश के अन्य हिस्सों के बराबर विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इन क्षेत्रों को अब नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है, जहां लोग न केवल बेहतर जीवन जी सकें, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका भी निभा सकें।

इस पूरे बदलाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत की सीमाएं अब केवल सुरक्षा की रेखा नहीं रह गई हैं, बल्कि वे विकास और समृद्धि के नए द्वार बनती जा रही हैं। यदि यह रणनीति सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में सीमावर्ती गांव देश के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं, जहां सुरक्षा और समृद्धि दोनों का संतुलन देखने को मिलेगा।

## संपादकीय

# मौतें सबसे स्वच्छ शहर पर कलंक

यह शर्मनाक है कि जिस शहर को पिछले सात सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा दिया जा रहा था, वहां पेयजल में सीवर का पानी मिल जाने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाए। बताया जाता है कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर के पानी के रिसाव से हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। घटनाक्रम के बाद सौ के करीब लोग अस्पताल में भर्ती हुए और सैकड़ों लोग दूषित पेयजल के उपयोग से बीमार हैं। वैसे भी किसी सभ्य समाज में व्यक्ति आत्मग्लानि से यह सुनकर बीमार हो जाएगा कि जिस पानी को उसने उपयोग किया, उसमें सीवर का गंदा पानी मिला था। निस्संदेह, यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही ही है, जिसके चलते हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। नगर निगम ही नहीं, इस महकमे से जुड़े सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल, इंदौर लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल करता रहा है तो इस दुर्घटना ने पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बना दिया। इस दुखद स्थिति के चलते मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिये बाध्य होना पड़ा। विडंबना यह है कि नागरिकों ने पहले ही दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत की थी, लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जवाबदेह अधिकारी तब हरकत में आए, जब कई लोगों की जान जा चुकी थी। यहां तक कि इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री, जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का महकमा आता है, उनकी संवेदनहीन बयानबाजी ने लोगों का आक्रोश बढ़ाया है। हालांकि, तल्ख आलोचना के बाद मंत्री ने खेद जताया है। यहां तक कि इस घटना के बाद मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने भी दोषियों से प्रायश्चित करने व दंड देने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ छोटे स्तर के अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण से इन मौतों के लिये जिम्मेदार लोगों का प्रायश्चित हो पाएगा?

लेकिन विडंबना है कि यह समस्या केवल इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के छोटे-बड़े शहरों में गाहे-बगाहे दूषित जल आपूर्ति के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। दुर्घटना के बाद जांच समितियों का गठन, मुआवजे की घोषणा और कनिष्ठ अधिकारियों का निलंबन मामले में लीपापोती का उपक्रम बन चुका है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सुधार, क्रियान्वयन और रूपांतरण' के मंत्र पर जोर दिया था। तब उन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जीवनयापन को सुगम बनाने के लिये प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। सवाल है कि जब नागरिकों को स्वच्छ हवा और जल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा जाएगा तो जीवनयापन को सुगम कैसे बनाया जा सकता है? मध्य प्रदेश की दोहरे इंजन वाली सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। कोई भी बड़ी योजना व नारा तब तक अर्थहीन है जब तक उन्हें जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का समर्थन प्राप्त न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद-21 के तरह जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इंदौर की त्रासदी दर्शाती है कि शहरी बुनियादी ढांचे के खराब रखरखाव के कारण इस अधिकार का उल्लंघन कितनी आसानी से हो सकता है। निष्कर्ष यह भी है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्मार्ट सिटी के दावे और शासन संबंधी नारे व्यवस्थागत नाकामी को छिपा नहीं सकते। इंदौर की घटना के बाद देश के सभी राज्यों में संबंधित विभागों व स्थानीय निकायों को पेयजल से जुड़ी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा कि कहीं पेयजल आपूर्ति लाइन जर्जर होकर दूषित पानी से तो नहीं मिल रही है। पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइप लाइनों का नियमित रूप से अवलोकन होना चाहिए। इस बाबत मंत्रालय और निकाय के अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे गंभीर मामलों में लापरवाही के दोषियों को सख्त सजा देने का भी प्रावधान होना चाहिए। यह मामला गैर इरादतन हत्या जैसा भी तो है।

# महिलाओं को लेकर डॉ कलाम का सपना अधूरा

> "आर्थिक भागीदारी में भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में केवल 18% है, जो काफी कम है। कामकाजी महिलाओं में से केवल 40-42% ही अपने पति के बराबर या उससे अधिक कमाती हैं। साक्षरता दर में 2010-2021 के बीच 14.4% की वृद्धि हुई है।

देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन के नाम मशहूर रहे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास की ओर ले जाता है। जब महिला सुखी होती है, तो घर सुखी होता है। जब घर सुखी होता है, तो समाज सुखी होता है, और जब समाज सुखी होता है, तो राज्य सुखी होता है, और जब राज्य सुखी होता है, तो देश में शांति होती है और उसका विकास अधिक गति से होता है। देश महिलाओं की मौजूदा हालात को देखते हुए लगता यही है डॉ कलाम का यह सपना पूरा नहीं हुआ है। इस सपने को पूरा करने के लिए अभी शायद दशकों तक इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर संसद में नेतृत्व तक का लंबा सफर तय किया है, फिर भी सच्ची समानता अभी भी दूर है। मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और महिला आरक्षण विधेयक एक बड़ी छलांग का वादा करता है। लेकिन लैंगिक भेदभाव, परोक्ष राजनीति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी व्यवस्थागत बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। विश्व स्तर पर भारत में महिलाओं की स्थिति मिश्रित है, जहाँ वे नेतृत्व और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, वहीं लैंगिक असमानता, सुरक्षा और श्रम भागीदारी में उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और साक्षरता में प्रगति के बावजूद, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और आर्थिक असमानता प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। जो महिलाओं की स्थिति में चिंताजनक गिरावट दर्शाता है।

देश में महिलाएं अभी तक लिंगभेद का शिकार हैं। महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और अपराधों के ग्राफ बताते हैं कि उनकी तरक्की ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं है। साल 2023 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 2023 में महिलाओं के खिलाफ 13,366 मामले दर्ज हुए, जो मुंबई में

6,025 और बेंगलुरु में 4,870 से कहीं ज्यादा हैं। हालांकि साल 2022 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। देश में 2021 से 2023 के बीच महिलाओं के खिलाफ कुल 13,21,745 अपराध दर्ज हुए। औसतन हर तीन मिनट में एक महिला किसी न किसी अपराध का शिकार हुई। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में पेश आंकड़ों के बताया कि ने घरेलू हिंसा, अपहरण, यौन अपराध और बाल शोषण जैसी घटनाओं में लगातार तीन वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई। उत्तर प्रदेश इन तीन वर्षों में सबसे आगे रहा, जहां 1,88,207 मामले दर्ज हुए। इसके बाद महाराष्ट्र में 1,31,958, राजस्थान 1,31,246, बंगाल 1,05,313 और मध्य प्रदेश में 95,780 मामलों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है। महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराधों में शामिल रहे पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 4,09,929 मामले तो वहीं अपहरण के 2,49,284 मामले सामने आए। गृह राज्य मंत्री बंदी ने बताया था कि अपराधों के ये रुझान सामाजिक और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करते हैं। विभिन्न राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों से जुड़े अपराधों की संख्या चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है। आर्थिक भागीदारी में भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों (82%) की तुलना में केवल 18% है, जो काफी कम है। कामकाजी महिलाओं में से केवल 40-42% ही अपने पति के बराबर या उससे अधिक कमाती हैं। साक्षरता दर में 2010-2021 के बीच 14.4% की वृद्धि हुई है। हालाँकि, केवल 10% महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णय खुद ले पाती हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2024 में 800 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। फिर भी, वैश्विक स्तर पर यह भागीदारी अभी भी कम है।

लोकनीति-सीएसडीएस के 2019 के 'महिलाएं और राजनीति' सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकतर महिलाओं को रैलियों में जाने, उम्मीदवार से मिलने या चुनाव प्रचार करने के लिए परिवार की मंजूरी लेनी पड़ती है। 58 प्रतिशत महिलाओं का मानना था कि राजनीतिक परिवार से आने वाली महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश आसान होता है। जबकि 57 प्रतिशत का मानना था कि आर्थिक रूप से मज़बूत परिवारों की महिलाओं को बढ़त मिलती है। अपने सर्वोच्च स्तर पर भी पहुंचकर भी महिलाओं का लोकसभा में हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत ही रहा, जबकि मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत है। 1952 में पहली लोकसभा में सिर्फ़ 22 महिलाएं चुनी गई थीं। 1977 में तो यह संख्या घटकर 19 ही रह गई। एक बड़ा बदलाव 21वीं सदी में दिखा। साल 2009 में 59 महिलाएं सांसद बनीं, 2014 में यह संख्या बढ़कर 62 हो गई, और 2019 में यह ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 78 तक पहुंच गई। 2024 में यह थोड़ा घटकर 74 रह गई।

राजनीतिक दल अक्सर कम टिकट देने को यह कहकर सही ठहराते हैं कि महिलाओं के जीतने की 'संभावनाएं' कमज़ोर होती हैं। लेकिन सफलता का आंकड़ा इस दावे को सवालों के घेरे में डाल देता है। 1957 में 49 प्रतिशत महिला उम्मीदवार जीतीं, जबकि पुरुषों में जीत का प्रतिशत सिर्फ़ 33 प्रतिशत था। 1962 में महिलाओं की सफलता दर 47 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की सिर्फ़ 25 प्रतिशत। हाल के चुनावों में भी महिलाओं की सफलता दर बराबर या थोड़ा बेहतर ही रही। वर्ष 2019 में 11 प्रतिशत जीतीं, जबकि पुरुषों में यह दर 6 प्रतिशत थी। 2024 में महिलाओं की सफलता दर 9 प्रतिशत और पुरुषों की 6 प्रतिशत रही।

इन आंकड़ों से साफ़ है कि जब महिलाओं को टिकट मिलता है तो वे चुनाव जीत सकती हैं। चाहे महिलाएं अब वोटिंग में लगभग बराबरी पर हों, लेकिन असली राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है। महिला आरक्षण बिल का पारित होना इस अंतर को कम करने का एक संरचनात्मक रास्ता ज़रूर खोलता है। आज भी 23% युवा महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, जो ग्रामीण और गरीब घरों में अधिक आम है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 46% है, " हालांकि, उनकी प्रभावी भागीदारी कम बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में, जहां अक्सर पुरुष रिश्तेदार निर्णय लेने में हावी रहते हैं।" इस प्रथा को उजागर करने और इसकी निंदा करने के लिए 'प्रधान पति' शब्द राजनीतिक शब्दावली में शामिल हो गया है।

यह दर्शाता है कि किस प्रकार गहरी जड़ें जमा चुके लैंगिक मानदंड प्रगतिशील कानूनों को कमजोर कर सकते हैं – परिवार और समुदाय सत्ता में महिलाओं को देखकर असहज महसूस कर सकते हैं, इसलिए वे पुरुषों को पर्दे के पीछे रखकर पुराने मानदंडों को लागू करते हैं। महिलाएं अब सेना, अंतरिक्ष, खेल और व्यावसायिक नेतृत्व में नए मानदंड स्थापित कर रही हैं। स्व-सहायता समूह, डिजिटल साक्षरता और शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों से बदलाव आ रहा है। इस गति को बढ़ाने की जरूरत है।

## प्रेरणा

# मीठे शब्दों की शक्ति और जीवन की सच्ची मिठास

मनुष्य के जीवन में कई ऐसे गुण होते हैं जो उसे दूसरों से अलग और विशेष बनाते हैं, लेकिन उन सभी गुणों में यदि किसी एक को सबसे अधिक प्रभावशाली कहा जाए तो वह है उसकी वाणी। वाणी केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन, उसके संस्कार और उसकी सोच का प्रतिबिंब होती है। किसी के शब्दों में यदि मिठास होती है तो वह बिना किसी विशेष प्रयास के ही लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से लेकर आज तक संतों और विद्वानों ने मधुर वाणी को सबसे बड़ी संपत्ति माना है।

एक बार एक ज्ञानी संत थे, जिनका नाम आत्मदेव था। उनके पास कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे, लेकिन उनमें से पांच शिष्य विशेष रूप से उनके निकट थे। ये सभी शिष्य अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे और उनके हर उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनते थे। एक दिन संत आत्मदेव ने सोचा कि क्यों न अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए, ताकि यह जाना जा सके कि उनमें से कौन वास्तव में उनके ज्ञान को सही रूप में समझ पाया है।

उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा कि अब समय आ गया है जब उनकी परीक्षा ली जाएगी। यह सुनकर सभी शिष्य उत्साहित हो गए और पूरी लगन के साथ परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उन्हें विश्वास था कि वे अपने गुरु की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

संत आत्मदेव ने उनसे एक सरल सा प्रश्न पूछा, लेकिन उस प्रश्न के भीतर गहरा अर्थ छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, "बताओ इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है?" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी को दो घंटे के भीतर इसका उत्तर देना होगा। प्रश्न सुनते ही शिष्यों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह तो बहुत आसान प्रश्न है।

पहले शिष्य ने बिना देर किए उत्तर दिया कि गन्ना सबसे मीठा होता है, क्योंकि उससे निकलने वाला रस बहुत स्वादिष्ट होता है। दूसरे शिष्य ने कहा कि शक्कर सबसे मीठी होती है, क्योंकि उसका उपयोग हर प्रकार की मिठाइयों में होता है। तीसरे शिष्य ने गुड़ को सबसे मीठा बताया और चौथे ने तरह-तरह की मिठाइयों का उदाहरण देकर उन्हें सबसे मीठा बताया। पांचवां शिष्य भी इन्हीं उत्तरों के आसपास अपनी बात कहने लगा।

संत आत्मदेव ने सभी के उत्तर ध्यान से सुने, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं आया। तब उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि तुम सभी ने जो उत्तर दिए हैं, वे केवल बाहरी दृष्टि से सही हैं, लेकिन वे इस प्रश्न के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी वस्तुएं केवल हमारी जीभ को कुछ समय के लिए मिठास देती हैं, लेकिन इनकी मिठास स्थायी नहीं होती।

इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य बताया कि इस संसार में सबसे मीठी चीज वाणी की मिठास है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, तो वह हर किसी के हृदय में स्थान बना लेता है। उसकी बातें सुनकर लोगों को आनंद मिलता है और वे उसके पास रहना पसंद करते हैं।

वाणी की मिठास का अर्थ केवल मीठे शब्द बोलना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारे शब्दों में सम्मान, सच्चाई और संवेदनशीलता हो। जब हम किसी से प्रेम और आदर के साथ बात करते हैं, तो हमारे शब्दों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि मधुर वाणी वाला व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है।

इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति की वाणी कठोर होती है, तो वह अनजाने में ही लोगों को अपने से दूर कर देता है। कटु शब्द किसी के दिल को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं और रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात या एक कठोर वाक्य वर्षों पुराने संबंधों को भी तोड़ देता है।

वाणी की मधुरता केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो मधुर वाणी में बात करता है, वह अपने कार्यक्षेत्र में भी अधिक सफल होता है। लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और उसके साथ काम करने में सहज महसूस करते हैं।

यह भी सत्य है कि वाणी की मिठास जन्म से नहीं आती, बल्कि इसे अभ्यास और आत्मसंयम से विकसित किया जा सकता है। हमें अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखें। जब हम क्रोध में होते हैं, तब हमारे शब्द अक्सर कठोर हो जाते हैं, लेकिन यदि हम उस समय स्वयं को नियंत्रित कर लें, तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं।

आज के समय में, जब जीवन बहुत तेज गति से चल रहा है और लोग तनाव में रहते हैं, तब वाणी की मधुरता और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। यदि हम अपने व्यवहार में थोड़ी सी भी मिठास जोड़ दें, तो हम अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बना सकते हैं। हमारी एक छोटी सी मधुर बात किसी के दिन को खुशियों से भर सकती है। वाणी की मिठास केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने लिए भी लाभकारी होती है। जब हम मधुर बोलते हैं, तो हमारे भीतर भी शांति और संतुलन बना रहता है। इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं।

अंत में यह कहा जा सकता है कि वाणी की मधुरता जीवन की सच्ची मिठास है। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल हमें दूसरों के करीब लाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। संत आत्मदेव की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि सच्ची मिठास किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे शब्दों में होती है। यदि हम अपनी वाणी को मधुर बना लें, तो हम न केवल अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आनंद और खुशियां भर सकते हैं। यही एक सफल और सार्थक जीवन की पहचान है।

# उत्तर कोरिया: दिखावटी चुनाव में तानाशाह की फिर बल्ले-बल्ले

2 करोड़ 66 लाख आबादी वाले अघोषित गुलाम मुल्क उत्तर कोरिया में 15वें 'सुप्रीम पीपल्स असेंबली' के संपन्न दिखावटी चुनाव में भी किम जोंग उन ने एकतरफा जीत हासिल करके फिर से अपने तानाशाह होने का परिचय न सिर्फ अपने देशवासियों को, बल्कि समूचे संसार को दे दिया है। सभी 687 सीटों पर उनके समर्पित लोग जीते हैं। मौजूदा चुनाव में भी उनके सामने ना कोई विपक्ष था और न ही कोई विरोधी? चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार के रूप में अपने चपरासी, नौकर, जीजा, बहनें और जी-हुजूरी करने पार्टी कार्यकर्ता-कर्मचारियों को टिकट देकर उतारा था। चुनाव में किम जोंग की दो छोटी बहनें किम यो-जोंग, चो सन-हुईन और जीजा किम नॉउ व योंग-वोन भी जीते हैं। गठित कैबिनेट में इन चारों को बड़ी जिम्मेदारी देंगे किम जोंग। उत्तर कोरिया में चुनाव का मतलब केवल कोरियाई आवाम के अनुशासन को चेक करना और सरकारी डेटा को अपडेट करना मात्र होता है। वहां जनता अपनी पसंद का न उम्मीदवार चुन पाती है और न वोट कर सकती है। वोट न करना देशद्रोह माना जाता है। नार्थ कोरियाई लोग किम जोंन का आदेश किसी भी सूरत में नहीं टालते। अगर वो कहें कि आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा, तो देशवासियों को हाँ में ही जवाब देना होता है। जब वो हंसते हैं, तो सबको हंसना पड़ता है। घर से दो दिन किसी को नहीं निकलना है, तो कोई नहीं निकलता। लॉकडाउन जैसी स्थिति वहां हो जाती है। ऐसी अजीबोगरीब शर्तों को नार्थ कोरियाई आवाम को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। उत्तर कोरियाई का संसदीय चुनाव का इतिहास 1948 से रहा है। तब, वहां श्रमिक पार्टी, चोंडो ईस्ट चांगु पार्टी, कोरियाई लोकतांत्रिक पार्टी, श्रमिक जन पार्टी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी व डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट पार्टी की धूम होती थी। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तानाशाह का ही चारों ओर बोलबाला है।

वहां, पिछला संसदीय चुनाव 10 मार्च 2019 को हुआ था। परंपरा प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव कराने की है, लेकिन हुए 7 साल बाद हैं। इस चुनाव में आदेश था कि सभी सरकार के पक्ष में वोट करें, देशवासियों ने उनके आदेशानुसार वोट डाले। वोटर टर्नआउट 99.99 प्रतिशत रहा, जिनमें उनके पक्ष में रिकॉर्ड 99.93 प्रतिशत वोटिंग हुई। पंजीकृत मतदाताओं में केवल 0.0037 प्रतिशत वोटरों ने चुनावी प्रक्रिया में किसी कारण हिस्सा नहीं लिया जिनमें ज्यादातर ऐसे लोग बताए जाते हैं जो चुनाव के वक्त या देश से बाहर थे या हारी बीमारी से पीड़ित थे। सरकारी मीडिया एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक 516 लोगों ने वोट नहीं डाले, जिनकी खोज पड़ताल जारी है। खोजने पर उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। घरों की तलाशी जारी है, हाथ पर लगे निशान की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर पूर्ववर्ती चुनावों की तरह इस बार भी तानाशाह शासक का बोलबाला पूरे संसदीय चुनाव के दौरान रहा।

गौरतलब है कि किम जोंग उन की 'वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया' लंबे समय से देश पर जबरिया काबिज है। भविष्य में उम्मीद भी नहीं दिखती, कि उन्हें या उनके पारिवारिक सदस्यों को कोई सत्ता से हटा भी पाएगा? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है। चुनाव में अगर कोई सरकारी कर्मचारी उनके पक्ष में वोट नहीं करता, उसे सेवा से बेदखल कर दिया जाता है। अगर पब्लिक ने वोट नहीं किया तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा करके सरेआम कोड़ों से पीटा जाता है। नार्थ कोरिया में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या कोई ऐसे मुल्क जैसी व्यवस्था नहीं है कि विरोध में वहां के लोग 'जेन-जी' जैसा आंदोलन कर सके। ऐसा सपने में भी कोई नहीं सोच करता। सोचेगा तो उसे जिंदा गाड़ दिया जाता है। पिछले साल अगस्त-2025 का वाक्या है जब किम जोंन उन अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे, तभी बीच में एक कर्मचारी ने चाय पीने को लेकर उनसे पूछ लिया। सजा के तौर पर जोंन ने उनकी जुबान और दोनों हाथ कटवा दिए थे। मौजूदा 2026 का आम चुनाव भी उत्तर कोरिया के अनूठे राजनीतिक ढांचे को दर्शाता है कि जहां हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार होता है, जो किम के नेतृत्व वाली सत्ता द्वारा पहले से ही चुन लिया जाता है। मतदान में उत्तर कोरिया के वोटर्स को सिर्फ हां या ना कहने का अधिकार मिलता है। चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा नहीं होता। नॉर्थ कोरिया वैश्विक पटल से तकरीबन कटा हुआ है। उसे न अर्थव्यवस्था से मतलब है और न ही किसी किस्म की तरक्की से? अपने मन की हुकुमत किम जोंन चलाते हैं। किम जोंन न किसी मुल्क का दौरा करते हैं और न उनके यहां कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है। एकाध मर्तबा कोई पहुंचा भी तो उसे सरेआम मारा-पीटा गया। कईयों को जान से भी हाथ धोना पड़ा? ग्लोबल स्तर पर बनीं तमाम कल्याणकारी समितियों का भी नॉर्थ कोरिया सदस्य नहीं है। उनके प्रतिनिधि भी कहीं प्रतिभाग नहीं करते। नॉर्थ कोरिया के अलावा रूस में भी ऐसी ही चुनावी प्रक्रिया है। वहां भी सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को अपने पक्ष में वोट करने का आदेश दिया जाता है। ब्लादीन पुतिन भी अपने जीते-जी सत्ता से नहीं हट सकते। इस दिशा में कुछ और भी राष्ट्ध्यक्ष चल पड़े हैं। तानाशाह शासक बेशक लोकतंत्र होने की दुहाई देते हों, लेकिन वो गुलाम बनाकर रखते हैं अपने आवाम को। नॉर्थ कोरियाई लोग कब तानाशाह से मुक्ति पाएंगे, ये सवाल भविष्य के गर्भ में सुरक्षित है। तारीख कौन सी मुकर्रर होगी, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। नॉर्थ कोरियाई लोग ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व में जनसंख्या के मामले में 56वें स्थान पर है। 2.66 लाख वाले इस मुल्क के लोगों को आजादी की सुबह कब होगी नसीब उसकी दुआ पूरा संसार करता है।

## अभियान

# यमुना महिमा और श्रीकृष्ण की दिव्य पटरानी का अलौकिक स्वरूप

सनातन धर्म की विशाल और गूढ़ परंपरा में नदियों को केवल जलधारा नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का स्वरूप माना गया है। इन्हीं दिव्य स्वरूपों में एक अत्यंत पूजनीय और पवित्र नाम है यमुना जी का, जिन्हें धर्मग्रंथों में परमब्रह्म श्रीकृष्ण की पटरानी के रूप में वर्णित किया गया है। यमुना केवल एक नदी नहीं हैं, बल्कि भक्ति, प्रेम, करुणा और मोक्ष का साक्षात प्रवाह हैं। उनका स्मरण मात्र ही मन को शुद्ध करता है और आत्मा को परम शांति प्रदान करता है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, यमुना जी का अवतरण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, जिसे पूरे भारतवर्ष में "यमुना जयंती" या "यमुना षष्ठी" के रूप में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह चैत्र नवरात्र के छठे दिन पड़ता है, जो शक्ति उपासना और सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हुआ पावन काल होता है। ऐसा मान्यता है कि इसी नवरात्र के प्रथम दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस जगत की रचना की थी और तृतीया तिथि को भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा की थी। षष्ठी तिथि को यमुना जी का अवतरण इस क्रम को पूर्णता प्रदान करता है, जिससे यह दिन अत्यंत शुभ और पावन बन जाता है।

यमुना जी का संबंध केवल एक पौराणिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका अस्तित्व श्रीकृष्ण की लीलाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजभूमि में अवतार लिया, तब यमुना जी उनकी बाल लीलाओं की साक्षी बनीं। मथुरा और वृंदावन की पावन भूमि पर श्रीकृष्ण ने यमुना के तट पर अपनी अनगिनत लीलाएं कीं, जिनमें कालिय नाग का मर्दन, गोपियों के साथ रास लीला और जल क्रीड़ाएं प्रमुख हैं। यमुना का श्यामल जल स्वयं श्रीकृष्ण के रंग से अभिन्न माना जाता है, जिससे उनका संबंध और भी गहरा हो जाता है।

यमुना जी का उद्गम स्थान उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित यमुनोत्री धाम है, जो हिंदुओं के चार धामों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहां से निकलकर यमुना जी उत्तर भारत के अनेक राज्यों से होती हुई अंततः प्रयागराज में गंगा और सरस्वती के संगम में मिल जाती हैं। इस त्रिवेणी संगम का स्नान विशेष पुण्यदायी माना जाता है और कहा जाता है कि यहां स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री हैं। उनकी माता का नाम संज्ञा या संजना बताया गया है, जो विश्वकर्मा की पुत्री थीं। इस प्रकार यमुना जी दिव्य वंश से संबंधित हैं। उनके भाई यमराज हैं, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, और शनिदेव उनके छोटे भाई हैं, जो कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार यमुना जी का परिवार भी धर्म और न्याय के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है।

यमुना जी को "कालिंदी" नाम से भी जाना जाता है। यह नाम उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उनका उद्गम कालिंदी पर्वत से हुआ है और उनके जल का रंग गहरा श्यामल होता है। यह श्यामलता केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह श्रीकृष्ण के प्रति उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। कालिंदी स्वरूप में यमुना जी ने स्वयं श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और अंततः भगवान ने उन्हें अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार किया।

ब्रजभूमि में यमुना जी का महत्व अत्यंत विशेष है। वहां के संत और रसिक भक्त उन्हें केवल एक नदी नहीं, बल्कि श्रीराधा-कृष्ण की लीलाओं की साक्षी और सहभागी मानते हैं। ब्रज के कुंजों, उपवनों और तटों पर यमुना जी ने उन दिव्य लीलाओं को देखा और संजोया है, जो आज भी भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति की भावना जागृत करती हैं। वल्लभ सम्प्रदाय के वार्ता साहित्य में भी यमुना जी के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें उनकी विभिन्न धाराओं और ब्रज क्षेत्र में उनके प्रवाह का उल्लेख किया गया है।

यमुना जी का आध्यात्मिक महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका दर्शन और स्पर्श भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि यमुना के जल में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मन और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। विशेष रूप से यमुना षष्ठी के दिन स्नान और पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

भारत के विभिन्न भागों में यमुना जयंती का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में इस दिन भव्य आयोजन होते हैं। मंदिरों को सजाया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है। भक्तजन यमुना जी की आरती करते हैं और उनके तट पर दीपदान करते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनोहारी और दिव्य होता है, जो हर किसी के हृदय को भक्ति से भर देता है।

गुजरात और अन्य राज्यों में भी यमुना षष्ठी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। वहां भी भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति और जल के महत्व को समझने का भी संदेश देता है।

आज के आधुनिक युग में, जब नदियां प्रदूषण और उपेक्षा का शिकार हो रही हैं, तब यमुना जी की महिमा को समझना और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। यदि हम वास्तव में उन्हें देवी मानते हैं, तो हमें उनके स्वच्छता और संरक्षण के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि यमुना जी केवल एक नदी नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष का सजीव प्रतीक हैं। उनका संबंध श्रीकृष्ण से उन्हें और भी दिव्य बना देता है। उनका स्मरण, उनका दर्शन और उनका पूजन हमारे जीवन को पवित्र और सार्थक बना सकता है। यदि हम उनके महत्व को समझें और उनके प्रति श्रद्धा रखें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी दिव्यता और शांति का संचार होगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# 'सुगम डिजिटल गुजरात' : लाइन से ऑनलाइन की ओर जन सुख-सुविधा का एक और कदम

**▸▸ विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात : टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुशासन का संकल्प**

**▸▸ मुख्यमंत्री की नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील**

**▸▸ डिजिटलाइजेशन वर्तमान भारत, वर्तमान गुजरात तथा वर्तमान नेतृत्व की देन है : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया**

**मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**

▸▸ हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जनता के काम आसानी से हों, लोगों के काम जितनी आसानी से होंगे, उतना ही शासन-प्रशासन को अधिक संतोष मिलेगा

▸▸ जनता, निर्वाचित जन प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी जब सभी स्तर पर साथ मिलकर काम करते हैं, तब परिणाम हमेशा अद्भुत एवं सटीक आता है

▸▸ सब साथ हैं, तो किसी को भी तकलीफ नहीं होने वाली है, राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है

**(जीएनएस)।** गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की गरिमामय उपस्थिति में मंगलवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में राज्य के प्रशासन को अधिक आधुनिक तथा नागरिक-केन्द्रित बनाने के उद्देश्य के साथ 'सुगम डिजिटल गुजरात' पहल का विधिवत् प्रारंभ कराया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' संकल्प को साकार करने तथा गुजरात के नागरिकों को सरकारी सेवाएँ उंगलियों पर उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है।

इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) की पाँचवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर राज्य के 5 प्रमुख विभागों की 20 हाईट्रांजेक्शन सेवाओं का ऑनलाइन सरलीकरण घोषित किया गया था। इस पहल द्वारा अब आय-जाति के प्रमाणपत्र, राशन कार्ड तथा शपथपत्र जैसी बुनियादी सेवाएँ 'फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस' बनेंगी।

मुख्यमंत्री ने 'सुगम डिजिटल गुजरात' अनावरण कार्यक्रम अंतर्गत कहा कि हम कई कार्यक्रम किया करते हैं और कार्यक्रम एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार जो कार्य करती है, वे लोगों तक पहुँचते हैं। इतना ही नहीं; सरकार का हमेशा यह प्रयास होता है कि जो कार्य किया गया है, उसमें कमी न रह जाए और प्रेस के माध्यम से वह जानकारी घर-घर पहुँचे, तो जो नागरिक सरकारी योजनाओं के पात्र हैं, वे उसका पूरा लाभ ले सकें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2002 में 'स्वागत ऑनलाइन' कार्यक्रम शुरू कर टेक्नोलॉजी के उपयोग को सदैव प्राथमिकता दी है। उसी प्राथमिकता के आधार पर आज हम बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और हम लगभग 20 नई सेवाएँ 'लाइन' से 'ऑनलाइन' करने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सभी लोगों को घर बैठे सुविधा मिले; इसके लिए फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार प्रयासरत है। इस डिजिटल प्रक्रिया में यदि नागरिकों को कहीं भी दिक्कत महसूस हो, तो उसके निवारण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण जनों के सबसे पहले पटवारी या विलेज कम्प्यूटर एंटरप्रेन्योर (वीसीई) के साथ ही संपर्क में आने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी सेवाएँ ऑनलाइन किस तरह मिलती हैं; उसका हम सभी जितना प्रचार-प्रसार करेंगे, उतना ही जनता को और प्रशासन को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "आप जो नौकरी या सेवा कार्य करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही दिशा में होना चाहिए कि जनता के काम आसान हों। हमारे मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जितनी आसानी से लोगों का काम हो, उतना हमें संतोष मिले। जब जन प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी सभी स्तर एक साथ मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं, तब उसका परिणाम अद्भुत आता है। गुजरात में हम सबने देखा है कि कैसी भी स्थिति हो, अगर हमने साथ मिलकर काम किया है, तो उसके सटीक परिणाम मिले हैं।"

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि जब प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट की बात की थी, तब कई लोगों को ऐसा लगता था कि यह कैसे संभव होगा, परंतु आज पूरे देश में सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट का उपयोग सामान्य नागरिक तथा छोटे से छोटे व्यक्ति कर रहे हैं। इसमें जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि जब सरकार समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रही हो, तब जनता का साथ हमेशा मिलता रहा है। आज 20 सेवाएँ ऑनलाइन की गई हैं और भविष्य में इस क्षेत्र में ध्यान देकर नागरिकों को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार तत्पर है।

उन्होंने बताया कि अनावृत हो रही इस नई पहल से स्थापित होने वाली व्यवस्था में डेटा डिजिटल होने के कारण नागरिक को हर नई सेवा के लिए बार-बार वही के पेपर प्रस्तुत नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए डिजिटल लॉकर की भी शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस उपयोग का लाभ जन-जन तक पहुँचे; इसके लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात' विजन को साकार करने के लिए हम सबको डिजिटल क्षेत्र में अधिक से अधिक आगे बढ़ना है। यूपीआई का सर्वाधिक उपयोग छोटे फेरीवाले तथा सब्जीवाले जैसे कम पढ़े-लिखे लोग कर रहे हैं। डिजिटल सरलीकरण के जरिये नागरिक सेवाएँ अधिकाधिक आसान बनाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने हाल में उत्पन्न हुई वैश्विक स्थिति के विषय में कहा कि आज राज्य में डीजल, पेट्रोल या गैस की कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और मिलता रहेगा। सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के कार्य मंत्र के साथ सरकार विकसित गुजरात के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सब साथ हैं, तो किसी को तकलीफ नहीं होगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि डिजिटलाइजेशन वर्तमान भारत, वर्तमान गुजरात तथा वर्तमान नेतृत्व की देन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब नागरिकों एवं सरकार के बीच दूरी कम करने के प्रयास शुरू किए गए थे। नागरिकों को जन हितकारी सुविधाएँ आसानी से मुहैया कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान किया गया था।

उन्होंने कहा कि गाँव में सीएससी, पीएससी तथा शहरी क्षेत्रों में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ये सेवाएँ तेजी से मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोढवाडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तमाम नागरिक-केन्द्रित सेवाएँ डिजिटल बनाने की शुरुआत की है। उन्होंने जोड़ा कि पहले दिल्ली से एक रुपया भेजा जाता, तो 15 या 16 पैसे ही नागरिकों तक पहुँचते; जबकि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुदृढ़वर्ती नागरिकों को सीधे डीबीटी के जरिये पूरी सहायता मिल रही है। इस बार बेमौसम वर्षा प्रभावित किसानों के खाते में एक क्लिक से लगभग 11000 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जबकि समर्थन मूल्य पर 15000 करोड़ रुपए की फसलें खरीदी गईं। इसके अलावा; 26 हजार करोड़ रुपए एक ही क्लिक से सभी लाभार्थियों के खाते में जमा हो गए। आज शायद यह डिजिटल सिस्टम न होता, तो पूरी राज्य सरकार के पाँच-छह लाख कर्मचारी इन कार्यों में लगाने पड़ते। आज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज की सेवाएँ, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति तथा विधवा बहनों की पेंशन जैसी सुविधाएँ डिजिटलाइजेशन होने के कारण आसान, पारदर्शी तथा त्वरित बनी हैं। ये सेवाएँ पूरी तरह डिजिटल नहीं हैं, कुछ दस्तावेज ऑफलाइन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यह पोर्टल कार्यरत होने से नागरिक घर बैठे अधिकांश सेवाओं के लिए फॉर्म स्वयं ही भर सकेंगे। 'नागरिक देवो भव' के भाव से वर्तमान सरकार के नेतृत्व में शुरू हुई इस डिजिटल सुविधाओं का योगदान विकसित भारत-2047 में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास ने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आग्रह है कि आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रमाणपत्रों के लिए सरकारी कार्यालयों में और सरकारी कार्य के लिए आने वाले लोगों की लाइनें खत्म होनी चाहिए। लोगों का काम घर बैठे होना चाहिए। हर वर्ष अस्सी लाख लोग कतार में खड़े रहें; यह उचित नहीं है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा सहित सभी विभाग अच्छा कार्य कर रहे हैं।

'सुगम डिजिटल गुजरात' की विशेषता के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों के काम घर बैठे होंगे। सरकारी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। नागरिकों को फोन में, व्हॉट्सएप पर सेवा मिलेगी। इसमें बारकोड है तथा आधार कार्ड आधारित ऑथेंटिकेशन है। यह सिस्टम इस तरह तैयार और विकसित किया गया है कि अगर एक साथ दस लाख लोग पोर्टल पर आ जाएँ, तो भी समस्या नहीं पैदा होगी। उन्होंने राज्य सरकार के ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रतिबद्ध होने का उल्लेख करते हुए नागरिकों से अनुरोध किया कि वे यदि सरकार को कोई नया सिस्टम विकसित करने की जरूरत हो, तो उसे लेकर सुझाव दें।

इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशिक्षण) के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला ने स्वागत संबोधन में कहा कि समग्र प्रक्रिया के मनोमंथन तथा अध्ययन रिपोर्ट के बाद ये टॉप 20 सर्विसेज नागरिकों की सुविधा के लिए कार्यान्वित की गई हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री मोना खंधार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती, राज्य सरकार के उच्चाधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार तथा पटवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

# सूरत में LPG संकट की आहट: प्रवासी मजदूरों की परेशानी पर चैंबर की चेतावनी, उद्योगों पर पड़ सकता है बड़ा असर

गुजरात के औद्योगिक हृदय माने जाने वाले सूरत में एक नई चिंता उभरकर सामने आई है, जो सीधे तौर पर शहर की अर्थव्यवस्था और लाखों मजदूरों के जीवन से जुड़ी हुई है। शहर में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों को घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन प्राप्त करने में आ रही गंभीर कठिनाइयों को लेकर सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में चैंबर ने जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी को पत्र लिखकर तत्काल समाधान की मांग की है।

सूरत देश के उन शहरों में शामिल है, जहां रोजगार के अवसरों के कारण हर साल हजारों लोग दूसरे राज्यों और जिलों से आते हैं। टेक्सटाइल, डायमंड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले इन श्रमिकों की संख्या कुल कार्यबल का लगभग 60 से 80 प्रतिशत तक मानी जाती है। लेकिन इन प्रवासी मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर खड़ी हो रही है, जिसमें घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन एक अहम मुद्दा बन गया है।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी के अनुसार, शहर में काम कर रहे अधिकांश प्रवासी मजदूरों के पास स्थानीय राशन कार्ड नहीं होता, जो कि वर्तमान व्यवस्था के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज माना जाता है। ऐसे में उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर एजेंसियों द्वारा कनेक्शन देने से मना कर दिया जाता है। इसका सीधा असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है, क्योंकि गैस जैसी आवश्यक सुविधा के बिना खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चैंबर ने प्रशासन के सामने एक व्यावहारिक सुझाव रखा है। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों को राशन कार्ड के बजाय आधार कार्ड के आधार पर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की जाए। आधार कार्ड आज एक मान्य और व्यापक पहचान पत्र है, जिसे देशभर में स्वीकार किया जाता है। यदि इस आधार पर कनेक्शन देने की अनुमति दी जाती है, तो लाखों मजदूरों को राहत मिल सकती है।

इस मुद्दे का एक और पहलू भी है, जो शहर की औद्योगिक संरचना से जुड़ा हुआ है। चैंबर ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि गैस की उपलब्धता और कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया गया, तो इसका असर सीधे मजदूरों की संतुष्टि पर पड़ेगा। पहले से ही कई क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में रुकावट और कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे मजदूरों में असंतोष बढ़ रहा है।

ऐसे हालात में यह आशंका भी जताई गई है कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया, तो प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों की ओर लौट सकते हैं। यह स्थिति सूरत जैसे औद्योगिक शहर के लिए बेहद चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि यहां के उद्योग काफी हद तक इन मजदूरों पर निर्भर हैं। टेक्सटाइल मिलें, डायमंड कटिंग यूनिट्स और छोटे-बड़े कारखाने इन श्रमिकों के बिना ठप पड़ सकते हैं।

सूरत की अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके बिना उत्पादन और व्यापार की गति धीमी पड़ सकती है। ऐसे में यह केवल एक सामाजिक या प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। चैंबर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से अपील की है कि इस विषय पर शीघ्र और प्रभावी कदम उठाए जाएं।

# सूरत में बार काउंसिल चुनाव की जीत पर वकीलों ने निकाली भव्य विजय रैली, कोर्ट परिसर में बना उत्सव का माहौल

गुजरात के सूरत शहर में बार काउंसिल ऑफ गुजरात के चुनाव में सूरत के वकीलों की जीत के बाद पूरे शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस खुशी के मौके पर सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को सूरत कोर्ट से अठवा गेट चौपाटी तक भव्य विजय रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में वकील, उनके समर्थक और स्थानीय समाज के लोग शामिल हुए।

रैली की शुरुआत सुबह के समय सूरत कोर्ट परिसर से हुई और ढोल-नगाड़ों की आवाज़ के बीच वकीलों ने उत्साहपूर्वक विजय रैली निकाली। महिला वकीलों ने गरबा खेलते हुए इस जश्न में भाग लिया, जिससे पूरे मार्ग पर रंग-बिरंगा और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। सीनियर और जूनियर वकीलों ने विजयी उम्मीदवारों का गर्मजोशी से स्वागत किया और एक-दूसरे को बधाई देते हुए आपसी सहयोग और एकता का संदेश दिया।

इस अवसर पर एडवोकेट प्रीति जिग्नेश जोशी ने कहा कि यह जीत वकीलों की एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बार काउंसिल में पारदर्शिता बनाए रखते हुए वकीलों के हितों के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि युवा और अनुभवी वकीलों के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ताकि सभी को समान अवसर और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

विजय रैली में प्रीति जिग्नेश जोशी, हिरल पानवाला, हितेश पटेल, भावेश रबारी, झकी शेख सहित अन्य विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थक शामिल हुए। रैली के दौरान सभी ने मिलकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में दिनभर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिससे पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा और वकीलों की इस सामूहिक सफलता की झलक हर तरफ देखने को मिली।

इस भव्य विजय रैली ने यह साबित किया कि सूरत के वकील न केवल पेशेवर एकता के प्रतीक हैं, बल्कि वे अपने अधिकारों और समुदाय के हितों के लिए सक्रिय और संगठित भी हैं। यह जश्न न केवल चुनाव की जीत का उत्सव था, बल्कि भविष्य में न्यायिक पेशे में पारदर्शिता, सुधार और सामूहिक प्रयासों की दिशा में एक मजबूत संदेश भी माना जा रहा है।

# अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन देने से बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर हो गई है

**(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।** गुजरात सरकार, गांधीनगर स्थित वित्त विभाग सचिवालय के संकल्प संख्या व्यय-102010-118-झ.1, दिनांक 14/08/2014 और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक 01/04/2010 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन दोनों संकल्पों को रद्द करने के लिए गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के पंजीकृत ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष छगनलाल डी. मेवाड़ा, महासचिव सैयदभाई शेख, महासचिव कांतिभाई सोलंकी, सूरत नगर शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष हसमुखभाई पटेल और अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 01/04/2010 के संकल्प के प्रावधानों के अनुसार, चालक और श्रेणी-4 चपरासी, चपरासी-कर्म-चालक, चपरासी-सह-परिचारक, माली, धोबी, चौकीदार आदि पदों पर भर्ती पर प्रतिबंध है। चपरासी-सह-चौकीदार, सफाईकर्मी, लिफ्टमैन, लिफ्ट अटेंडेंट, सफाईकर्मी, वार्डबॉय, ड्रेसर, आया, क्लीनर, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, स्ट्रेचर बेयरर, वाटर बेयरर, हेल्पर, मुकदम, कुक, असिस्टेंट कुक, पोर्टर, हीरो, हवलदार और ऐसे ही अन्य पदों को आउटसोर्स किया जाना चाहिए। इसी कारण गुजरात राज्य में श्रेणी-4 के पदों की भर्ती पर रोक लगी हुई है। जिसके चलते राज्य सरकार में उपरोक्त पदों को लंबे समय से खाली रखा गया है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़ रही है जो इन पदों पर नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि इन पदों पर अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा ही कार्यरत हैं। राज्य सरकार में ऐसे लाखों पद खाली पड़े हैं। जिसके चलते राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। इस स्थिति में गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस ने उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को रद्द करने की मांग की है। गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायक निर्वाचित होने के बाद समाज के युवाओं की बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं करते। गुजरात सरकार में बड़ी संख्या में श्रेणी-4 के पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती 2010 से रुकी हुई है, फिर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित विधायक वर्षों से कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। इसलिए, इस मामले ने माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।

# गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम ही रहेगा, सरकार ने 10 किलोग्राम के बारे में फैली अफवाहों को गलत बताया

**(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।**

केंद्र सरकार ने पिछले एक सप्ताह से देश भर में गैस सिलेंडरों को लेकर फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि गैस सिलेंडर में केवल सामान्य मात्रा में गैस यानी 14.2 किलोग्राम ही होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस प्रकार, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि खाना पकाने के गैस सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम गैस भरी जाएगी। ऐसी खबरों के पीछे यह तर्क दिया गया था कि अगर सिलेंडर का वजन कम किया जाए तो अधिक लोगों को गैस की आपूर्ति की जा सकेगी। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सरकार से पूछा गया कि क्या वह गैस सिलेंडरों की क्षमता घटाकर 10 किलोग्राम करने पर विचार कर रही है, तो सरकार ने कहा कि ऐसा कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है। लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी खबरें भ्रामक और अफवाहें हैं।

# बेस्ट राइटर का ऐवॉर्ड पाने वाले टीचर

गुजरात स्टेट चिल्ड्रन्स लिटरेचर एकेडमी का सालाना कन्वेंशन 22 फरवरी 2026 को गुजरात विश्वकोष भवन में हुआ। इसमें साल 2023-2024 में पब्लिश हुई चिल्ड्रन्स लिटरेचर की किताबों में से बेस्ट किताबें चुनी गईं और उनके लेखकों को अवॉर्ड दिया गया। जिसमें, मॉडर्न चिल्ड्रन्स राइटर के तौर पर मशहूर श्री निकेताबेन व्यास को उनकी कॉमिक चिल्ड्रन्स स्टोरी बुक 'गंगुना पराक्रमो' के लिए शील्ड और कैश प्राइज के साथ कुसुमबेन भूपेंद्रभाई दवे बेस्ट राइटर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

गुजरात स्टेट टेक्स्टबुक बोर्ड और समग्र शिक्षा अभियान के साथ राइटर और रिव्यूअर के तौर पर काम करने वाली श्री निकेताबेन व्यास ने अपने यूनिक तरीके से चिल्ड्रन्स लिटरेचर को एजुकेशनल किताबें - गुजराती सीखो पार्ट 1, गुजराती सीखो पार्ट 2, चित्रवर्ता सीरीज पार्ट 1 से 10, सचित्र प्रज्ञा रीडिंग सीरीज - दी हैं। इसके अलावा, उन्होंने गंगू का पराक्रम (बच्चों की हास्य कहानियाँ), चीकू और सात जादूगरनी (टीनएज एडवेंचर स्टोरी), सुगंधवाली अँगूठी (बच्चों की कहानियाँ), बिल्ली नो फोटो छपायों खोटो (बच्चों की कहानी), बकाना गतकडा (हास्य व्यंग्य कहानियाँ), नेशनल हाईवे (सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल) जैसी किताबों के ज़रिए मातृभाषा के प्रचार-प्रसार में अनोखा योगदान दिया है। उनकी रचनाएँ कई बच्चों की मैगज़ीन जैसे फुलवाड़ी, बाल सृष्टि, बाल दुनिया, बाल भास्कर, जगमग वगैरह में रेगुलर छपती रहती हैं।

श्री निकेताबेन व्यास, जिन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए 5 जनवरी 2026 को गुजरात राज्य की माननीय शिक्षामंत्री श्रीमती रीवाबा जडेजा ने साहित्य साधना अवॉर्ड से सम्मानित किया है, अभी एलिसब्रिज स्कूल नंबर 30, स्कुलबोर्ड अहमदाबाद में टीचर के तौर पर काम कर रही हैं।

# क्रूड ऑयल वायदा में 289 रुपये की वृद्धि: सोना वायदा 426 रुपये बढ़ा, चांदी वायदा में 1026 रुपये की नरमी

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 567764.5 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 46522.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 521238.47 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 34465 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4579.18 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 37155.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 138411 रुपये के भाव पर खूलकर, 140800 रुपये के दिन के उच्च और 136292 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 139260 रुपये के पिछले बंद के सामने 426 रुपये या 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ 139686 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 74 रुपये या 0.06 फीसदी औंधकर 113994 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 20 रुपये या 0.14 फीसदी औंधकर 14283 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 137990 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 140880 रुपये और नीचे में 136312 रुपये पर पहुंचकर, 250 रुपये या 0.18 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 139733 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 136256 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 140900 रुपये और नीचे में 136256 रुपये पर पहुंचकर, 139750 रुपये के पिछले बंद के सामने 5 रुपये या 0 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 139755 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 218628 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 227470 रुपये और नीचे में 213562 रुपये पर पहुंचकर, 225167 रुपये के पिछले बंद के सामने 1026 रुपये या 0.46 फीसदी गिरकर 224141 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 1404 रुपये या 0.61 फीसदी घटकर 228686 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 1594 रुपये या 0.69 फीसदी गिरकर 228700 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 3086.22 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 5.4 रुपये या 0.48 फीसदी गिरकर 1115.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 5 पैसे या 0.02 फीसदी की नरमी के साथ 310.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 35 पैसे या 0.11 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 331.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 25 पैसे या 0.13 फीसदी की नरमी के साथ 187.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

**▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 46522.66 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 521238.47 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 37155.62 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34465 पॉइंट के स्तर पर**

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5948.35 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 8600 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8709 रुपये और नीचे में 8403 रुपये पर पहुंचकर, 289 रुपये या 3.46 फीसदी बढ़कर 8634 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 287 रुपये या 3.44 फीसदी की मजबूती के साथ 8637 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 274.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 277.7 रुपये के दिन के उच्च और 272.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 272.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.8 रुपये या 1.03 फीसदी की मजबूती के साथ 275.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 2.8 रुपये या 1.03 फीसदी की तेजी के संग 275.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 1015 रुपये के भाव पर खूलकर, 4.1 रुपये या 0.41 फीसदी की तेजी के संग 996.3 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 24860.69 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 12294.92 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2653.12 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 218.25 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 12.68 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 194.89 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4368.81 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1563.36 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 8.27 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 2.03 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9016 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 58349 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 29257 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 370504 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 64993 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7203 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19388 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 75186 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16797 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 24769 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा 33754 पॉइंट पर खूलकर, 34465 के उच्च और 33754 के नीचले स्तर को छूकर, 148 पॉइंट बढ़कर 34465 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 8500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 150.2 रुपये की बढ़त के साथ 918.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 275 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.3 रुपये की गिरावट के साथ 3.05 रुपये हुआ।

सोना मार्च 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 496.5 रुपये की गिरावट के साथ 75.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 391.5 रुपये की गिरावट के साथ 685.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.05 रुपये की गिरावट के साथ 17.24 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 59.2 रुपये की गिरावट के साथ 212.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.95 रुपये की गिरावट के साथ 1.2 रुपये हुआ।

सोना मार्च 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 399.5 रुपये की गिरावट के साथ 154.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 263.5 रुपये की बढ़त के साथ 1333 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.59 रुपये की बढ़त के साथ 29.15 रुपये हुआ।

# सूरत: सार्वजनिक विश्वविद्यालय ने इंडिया एक्सेलरेटर के साथ MoU पर हस्ताक्षर कर स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने की पहल की

सूरत : सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सूरत ने इंडिया एक्सेलरेटर के साथ रणनीतिक साझेदारी करते हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो छात्रों, उद्यमियों और नवाचार के क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाओं और अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वाइस-चेयरमैन-2 श्री अजीत शाह और प्रोवोस्ट डॉ. किरण पंड्या की उपस्थिति रही। इस साझेदारी का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को कम करना, अकादमिक नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है।

डॉ. किरण पंड्या ने कहा कि यह सहयोग छात्रों के नवाचार और उद्यमिता कौशल को निखारने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका लक्ष्य केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया की जरूरतों और वैश्विक बाजार की मांग के अनुसार छात्रों को सक्षम बनाना है। इंडिया एक्सेलरेटर, भारत के प्रमुख फंड-लेड स्टार्टअप एक्सेलरेटर में से एक है, जो मेंटरशिप, फंडिंग,

नेटवर्किंग और उद्योग विशेषज्ञता के जरिए स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। इस सहयोग से सार्वजनिक विश्वविद्यालय में इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स को एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स तक पहुंच मिलेगी, जिससे उनके व्यावसायिक आइडियाज को व्यावहारिक और बाजार-उपयोगी समाधान में परिवर्तित किया जा सकेगा।

MoU के तहत विश्वविद्यालय और इंडिया एक्सेलरेटर मिलकर स्टार्टअप्स के लिए संरचित मेंटरिंग, प्रगति की नियमित समीक्षा, उद्योग विशेषज्ञों और निवेशकों से मार्गदर्शन, फंडिंग, नेटवर्किंग और मार्केट एक्सेस जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा, छात्रों को एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स और स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे उन्हें उद्योग का वास्तविक अनुभव मिलेगा और उनके नवाचार पहलों को व्यावसायिक रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। इस साझेदारी में छात्रों और नवप्रवर्तकों के लिए नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और स्टार्टअप डेमो डे का आयोजन भी शामिल होगा, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों तथा उद्योग विशेषज्ञों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का अवसर मिलेगा।

इस सहयोग के अंतर्गत उभरते क्षेत्रों में सेक्टर-विशिष्ट एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स का विकास भी किया जाएगा, जो विशेष तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को आवश्यक मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स के लिए एलुमनाई-ड्रिवन फंडिंग सपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पहले से स्थापित उद्यमी और निवेशक अपने अनुभव और वित्तीय संसाधनों के माध्यम से नए स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन कर सकेंगे। इस साझेदारी के माध्यम से छात्रों के नवाचार पहल को व्यावसायिक रूप देने के लिए संरचित समर्थन मिलेगा, जिससे उनके आइडियाज बाजार में सफल हो सकेंगे और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे। यह सहयोग न केवल विश्वविद्यालय के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार के लिए स्थायी आधार तैयार करेगा। इस MoU के तहत अकादमिक संस्थान, उद्योग विशेषज्ञ, निवेशक और स्टार्टअप समुदाय मिलकर छात्रों को व्यावहारिक अनुभव, वित्तीय समर्थन, नेटवर्किंग और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए काम करेंगे। इससे छात्रों की स्टार्टअप पहलों को व्यावसायिक रूप देने में मदद मिलेगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग आने वाले वर्षों में नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, और क्षेत्र में प्रभावशाली उद्यमों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सार्वजनिक विश्वविद्यालय और इंडिया एक्सेलरेटर के प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता ज्ञापन छात्रों को गतिशील स्टार्टअप परिदृश्य में सफलता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, अवसर और सहयोग प्रदान करेगा।

इस पहल से सूरत और गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा और गति मिलेगी, जिससे छात्रों और उद्यमियों के बीच तालमेल, सामूहिक विकास और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होगी। इस साझेदारी का दीर्घकालिक प्रभाव यह होगा कि नवप्रवर्तक और उद्यमी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे, जिससे क्षेत्र में स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।

## फर्जी रेल टिकटों के विरुद्ध सघन जांच में अहमदाबाद मंडल को बड़ी सफलता,यात्रियों की सुरक्षा एवं पारदर्शी टिकटिंग प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु कड़ी कार्रवाई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा, मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में चलाए गए टिकट जांच अभियान के दौरान फर्जी रेल टिकटों के एक संगठित मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया गया है। यह कार्रवाई यात्रियों के हितों की सुरक्षा तथा रेलवे की पारदर्शी एवं विश्वसनीय टिकटिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिनांक 21 मार्च 2026 को प्रयागराज–अहमदाबाद एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22968) के अहमदाबाद स्टेशन पर आगमन के दौरान नियमित टिकट जांच में तैनात टिकट जांच स्टाफ श्री नीरज मेहता, श्री साजी फिलिप एवं उनकी टीम द्वारा सतर्कता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए संदिग्ध यात्रियों को रोका गया। गहन जांच के दौरान दोनों यात्रियों के टिकटों का सीरियल नंबर एक समान पाया गया। तत्पश्चात क्यूआर कोड स्कैनिंग एवं तकनीकी सत्यापन में यह स्पष्ट हुआ कि टिकटों की प्रतियां अनधिकृत रूप से तैयार की गई थीं। इस प्रकरण में अहमदाबाद की टीम द्वारा 15 व्यक्ति पकड़े गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अलर्ट जारी किया गया तथा संबंधित विभागों एवं नियंत्रण कक्ष को सूचित कर समन्वित कार्रवाई प्रारंभ की गई। आगे की जांच में यह तथ्य सामने आया कि असली टिकटों को स्कैन कर उनकी कई प्रतियां तैयार कर यात्रियों को अवैध रूप से बेचा जा रहा था। यह कृत्य प्रयागराज में एटीवीएम (ATVM) फैसिलिटेटर्स के लिए नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था, जिससे न केवल यात्रियों के साथ धोखाधड़ी हो रही थी, बल्कि रेलवे राजस्व को भी क्षति पहुंचाई जा रही थी।

अहमदाबाद मंडल द्वारा इस प्रकरण में संबंधित एजेंसियों के सहयोग से त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। दिनांक 21/22 मार्च की रात्रि लगभग 10:00 बजे से प्रातः 4:00 बजे तक अहमदाबाद स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनु त्यागी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी रखी गई तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयागराज में विजिलेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वित छापेमारी की गई।

इस दौरान सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर फर्जी टिकटों पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों की पहचान की गई। पकड़े गए 15 व्यक्तियों को सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने पर उन्होंने अलग-अलग दो व्यक्तियों की पहचान की, जिनसे उन्होंने टिकट खरीदे थे। जांच में इन व्यक्तियों के नाम विनय शुक्ला एवं गौरव पांडे सामने आए।

आगे की जांच में यह भी पाया गया कि फैसिलिटेटर विनय शुक्ला ने दिनांक 20 मार्च को प्रयागराज टी-8 टर्मिनल से अहमदाबाद के 6 तथा सूरत के 5 असली टिकट निकाले थे, जिन्हें उसने अपने साथी फैसिलिटेटर गौरव पांडे को सौंपा। गौरव पांडे इन टिकटों को लेकर चौंक क्षेत्र में अपने सहयोगी फरहाद के पास पहुंचा, जहां महंगे स्कैनर एवं फोटोशॉप सेटअप की सहायता से इन टिकटों की हूबहू प्रतियां (प्रत्येक की 10-10 कॉपी) तैयार की गईं। इसके पश्चात शातिरों द्वारा असली टिकटों को काउंटर पर वापस जमा कर राशि का रिफंड प्राप्त कर लिया गया, जबकि उनकी तैयार की गई नकली प्रतियां यात्रियों को मूल मूल्य पर बेच दी गईं। इस प्रकार आरोपियों ने अवैध लाभ अर्जित करते हुए रेलवे राजस्व को क्षति पहुंचाई।

उक्त प्रकरण में गौरव पांडे, विनय शुक्ला एवं फरहाद के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अहमदाबाद मंडल के अधिकारियों ने टिकट जांच स्टाफ की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं टिकटिंग प्रणाली की शुचिता के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार की अनियमितताओं के विरुद्ध भविष्य में भी सतत निगरानी एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे केवल अधिकृत रेलवे काउंटर, अधिकृत एजेंट अथवा आधिकारिक डिजिटल माध्यमों के माध्यम से ही टिकट प्राप्त करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे प्रशासन को दें।

## पश्चिम रेलवे द्वारा 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09622/09621 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर स्पेशल को 27 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09621 अजमेर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 26 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

2. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी स्पेशल को 12 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 11 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09706/09705 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर स्पेशल को 13 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09705 जयपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 12 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

4. ट्रेन संख्या 04728/04727 वलसाड–हिसार साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 04728 वलसाड–हिसार स्पेशल को 16 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04727 हिसार–वलसाड स्पेशल को 15 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09622, 04828, 09706 एवं 04728 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 26.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

## भावनगर रेलवे मंडल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 24 मार्च 2026 को रेलवे कम्युनिटी हॉल, भावनगर परा में एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, जिसमें अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा, सचिव श्रीमती माया त्रिपाठी एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन प्रमुख रूप से शामिल रहे।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण एवं प्रासंगिक उद्बोधन प्रस्तुत किए गए, साथ ही नारी के महत्व को चित्रित करते हुए एक गीत भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर रेलवे कर्मचारियों की बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे पोस्टर/ड्रॉइंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। मंडल कार्यालय में कार्यरत महिला संविदा कर्मियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिलाओं की भूमिका, उनकी उपलब्धियों एवं समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डाला तथा महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंत में आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ।

## अहमदाबाद मंडल का माल लदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन,50 मिलियन टन का आंकड़ा किया पार

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माल लदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 23 मार्च 2026 तक 50.10 मिलियन टन (MT) का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 मिलियन टन अधिक है, जो मंडल की सतत प्रगति एवं कार्यकुशलता को दर्शाता है।मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में अहमदाबाद मंडल के परिचालन एवं वाणिज्य विभागो की टीम द्वारा अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों—जैसे रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, त्वरित निर्णय प्रक्रिया एवं संसाधनों का इष्टतम उपयोग—ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में मंडल द्वारा 50.38 मिलियन टन का सर्वोच्च लदान दर्ज किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनः 50 मिलियन टन का आंकड़ा पार करना अहमदाबाद मंडल की निरंतर प्रगति एवं उच्च कार्य निष्पादन क्षमता को दर्शाता है।

अहमदाबाद मंडल द्वारा मालगाड़ियों के सुचारु एवं समयबद्ध संचालन, रेक की प्रभावी उपलब्धता एवं उपयोग, टर्नअराउंड समय में कमी तथा लोडिंग-अनलोडिंग प्रक्रियाओं के कुशल प्रबंधन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। साथ ही, ग्राहकों के साथ सतत संवाद, नई संभावनाओं की पहचान एवं ग्राहक-अनुकूल सेवाओं के विस्तार से माल लदान में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की गई है।

अहमदाबाद मंडल द्वारा कोयला, सीमेंट, उर्वरक, कंटेनर एवं पेट्रोलियम उत्पादों सहित विभिन्न वस्तुओं के लदान में निरंतर

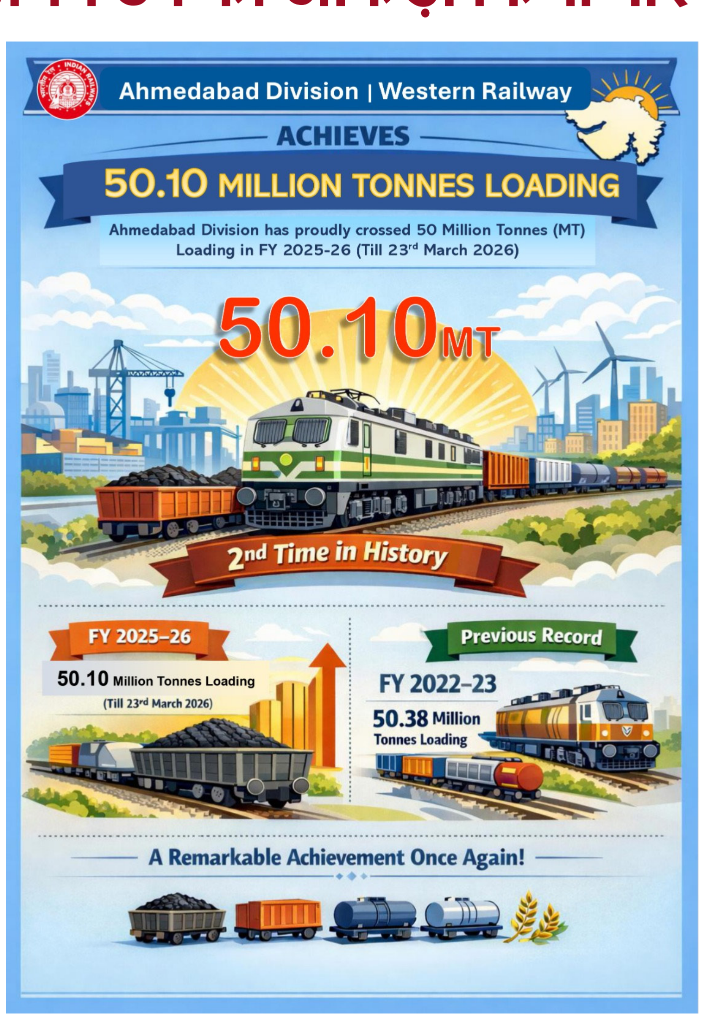


वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे न केवल रेलवे के राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि क्षेत्रीय औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिली है।

यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे की "परिचालन उत्कृष्टता, ग्राहक संतुष्टि एवं सतत विकास" की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है एवं यह उपलब्धि मंडल की सुदृढ़ कार्यप्रणाली, कुशल प्रबंधन एवं समन्वित प्रयासों का प्रतिफल है।

## भावनगर रेलवे मंडल में 'चालक दल हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे' सफलतापूर्वक संपन्न

(जीएनएस)। रेल कर्मचारियों के कार्य-संतोष एवं कार्य-परिस्थितियों के आकलन हेतु भावनगर मंडल द्वारा "चालक दल हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सर्वे का उद्देश्य रनिंग स्टाफ (चालक दल) के बीच संतुष्टि स्तर को मापना तथा कार्यस्थल पर सुधार के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करना था। सर्वे के परिणामों के अनुसार विभिन्न स्टेशनों/लोको शेड्स पर चालक दल संतुष्टि का स्तर अत्यंत उत्साहजनक रहा। प्रमुख स्थानों पर प्राप्त प्रतिशत इस प्रकार हैं— जूनागढ़ लॉबी– 97.29%, बोटाद लॉबी– 90.17%, सुरेन्द्रनगर गेट लॉबी @सुरेन्द्रनगर स्टेशन– 89.46%, पोरबंदर लॉबी– 88.43%, भावनगर टर्मिनस लॉबी– 87.42%, वेरावल लॉबी– 86.76%, JCLR लॉबी @ राजकोट स्टेशन 86.70% और जेतलसर लॉबी– 82.50% ।

इन परिणामों से स्पष्ट है कि भावनगर मंडल में कार्यरत चालक दल के बीच संतोष का स्तर उच्च है, जो सुरक्षित एवं कुशल रेल संचालन के लिए सकारात्मक संकेत है।

मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक (ADRM) श्री ऋत्विक शर्मा ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सर्वे से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ, ताकि कर्मचारियों के कार्य वातावरण को और बेहतर बनाया जा सके।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रकार के सर्वे भविष्य में भी नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे कर्मचारियों की अपेक्षाओं को समझकर संगठनात्मक दक्षता को और सुदृढ़ किया जा सके।

## होर्मुज के साये में भी सुरक्षित भारत की रसोई: 92 हजार टन LPG के साथ बढ़ता भरोसा और कूटनीति का संतुलन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच जब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितताएं गहराने लगती हैं, तब सबसे बड़ी चिंता उन देशों की होती है जो बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है, जहां रसोई गैस यानी एलपीजी करोड़ों घरों की जरूरत है। ऐसे संवेदनशील समय में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि Strait of Hormuz में तनाव के बावजूद देश की एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और फिलहाल किसी भी प्रकार का तात्कालिक संकट नहीं है। हाल के दिनों में ईरान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा कर दी थीं। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस परिवहन मार्गों में से एक है, वहां किसी भी प्रकार की बाधा का असर सीधे वैश्विक बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी संतुलित रणनीति और मजबूत लॉजिस्टिक्स के दम पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाए रखा है। राजेश सिन्हा, जो शिपिंग मंत्रालय में विशेष सचिव हैं, ने प्रेस वार्ता में साफ किया कि समुद्री मार्गों पर किसी भी देश द्वारा टैक्स या लेवी लगाए जाने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे किसी भी कदम की अनुमति नहीं है और वैश्विक व्यापार को बाधित करने की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। यह बयान न केवल घरेलू स्तर पर भरोसा बढ़ाने वाला है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी एक स्पष्ट संदेश देता है कि स्थिति नियंत्रण में है। सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' नामक दो भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर चुके हैं। इन जहाजों में कुल 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इन टैंकरों पर लगभग 60 भारतीय नाविक सवार हैं, जिनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये जहाज 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे, जिससे घरेलू आपूर्ति को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, वर्तमान में होर्मुज क्षेत्र में भारत के झंडे वाले लगभग 20 जहाज मौजूद हैं, जिनमें से सभी सुरक्षित हैं। इनमें 5 टैंकर एलपीजी से भरे हुए हैं, जिनमें करीब 2.30 लाख मीट्रिक टन गैस है। एक अन्य टैंकर लोडिंग प्रक्रिया में है, जो यह दर्शाता है कि भारत की आपूर्ति श्रृंखला न केवल सक्रिय है, बल्कि निरंतर गतिशील भी बनी हुई है। सरकार इन सभी जहाजों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है।

यह पूरा परिदृश्य इस बात को भी रेखांकित करता है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से काम किया है। विविध स्रोतों से आयात, रणनीतिक भंडारण और मजबूत समुद्री नेटवर्क ने देश को ऐसी परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखने में मदद की है। एलपीजी जैसे आवश्यक ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आम जनता के दैनिक जीवन से है।

कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। रणधीर जायसवाल, जो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं, ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत विभिन्न देशों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है। शीर्ष स्तर पर संपर्क और बातचीत के जरिए स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह कूटनीतिक सक्रियता न केवल भारत के हितों की रक्षा करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी जिम्मेदार भूमिका को भी दर्शाती है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत ने केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वैश्विक तनाव के संकेत मिलते ही आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी बढ़ा दी गई थी और वैकल्पिक मार्गों तथा स्रोतों पर भी ध्यान दिया गया। यही कारण है कि जब अन्य देशों में ऊर्जा संकट की आशंका जताई जा रही है, तब भारत अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और भू-राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ता है। ऐसे में भारत का यह संतुलित और सक्रिय दृष्टिकोण एक मजबूत उदाहरण के रूप में सामने आता है। यह दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। हालांकि, फिलहाल सरकार के आश्वासन और जमीनी स्तर पर दिख रही तैयारियों से यह स्पष्ट है कि भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है।